3 कांग्रेस ने कालेज प्रबंधन पर लगाए आरोप

5 राजनीति में प्रभावशाली नेता हैं सोनिया गांधी

7 बिहार की 75 लाख महिलाओं को 7500 करोड़

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 21 प्रति सोमवार, 29 सितंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी गोविंद सिंह राजपूत पर छाया मंत्री पद जाने का सियासी तूफान

संपत्ति छुपाने के आरोपों में हाईकोर्ट की लताड़, मुख्यमंत्री तक घिरे सवालों में

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़ा सियासी भूचाल आया हुआ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सिर पर संकट के बादल इस कदर गहराए हुए हैं कि मंत्री पद ही खतरे में नजर आ रहा है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों, विपक्ष की तल्ख आलोचनाओं और अंदरूनी पार्टी राजनीति के ताजे घटनाक्रमों ने राजपूत की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। संपत्ति छुपाने के आरोपों में हाईकोर्ट ने न सिर्फ गोविंद सिंह राजपूत को फटकार लगाई है, बल्कि उनके पक्ष में खड़ी होने वाली राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, को भी दो टूक सुनाई है। अब जब कोर्ट ने इस मामले में गंभीर रुख अपनाया है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद से हाथ धो बैठेंगे? इससे पहले भी राजपूत और उनके भाई पर कई तरह के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं।

क्या वाकई छुपाई संपत्ति?

मामले की जड़ में है गोविंद सिंह राजपूत का चुनावी हलफनामा, जिसमें कथित रूप से उन्होंने अपनी सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। आरोप यह है कि राजपूत ने जानबूझकर अपनी कुछ संपत्तियों को सार्वजनिक घोषणा से छिपा लिया। इस मुद्दे को अदालत तक पहुंचाया गया और हाल ही में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यदि मंत्री ने जानबूझकर जनता और चुनाव आयोग को गुमराह करने की कोशिश की है, तो यह गंभीर मामला है, जो उनकी विधायकी और मंत्री पद दोनों पर असर डाल सकता है।

(शेष पेज 2 पर)

कड़क छवि और सटीक कार्यशैली वाले अफसर के कंधों पर अब प्रशासनिक चुनौतियों का भार

छत्तीसगढ़ को मिला नया मुख्य सचिव विकास शील, बने राज्य के 12वें मुख्य सचिव

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ को नया मुख्य सचिव मिल गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकास शील को राज्य का 12वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे अपनी कड़क छवि, सटीक कार्यशैली और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के करीबी अफसरों में गिने जाने वाले विकास शील को अब राज्य की प्रशासनिक बागडोर संभालने का जिम्मा सौंपा गया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब राज्य कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है आर्थिक प्रबंधन से लेकर नक्सलवाद, बेरोजगारी, और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन तक। विकास शील के लिए यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वे प्रशासन में नया अनुशासन और स्पष्टता लेकर आएंगे।

प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव

विकास शील भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अनुभवी अधिकारी हैं और अब तक केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के अधिकारी हैं और पिछले दो दशकों में उन्होंने कई प्रमुख विभागों में प्रभावी कार्य किया है। (शेष पेज 2 पर)

विश्वास सारंग ने मछली परिवार को बनाया गुनाहों का मगरमच्छ

क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल करेंगे विश्वास सारंग के खिलाफ कार्रवाई?

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में इस समय जिस प्रकरण ने सनसनी मचाई है, वह है सारिक मछली और यासीन मछली कांड। यह मामला केवल अपराधियों की करतूत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो राजनीतिक संरक्षण की परतें सामने आ रही हैं, उसने शासन-प्रशासन की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिंह खड़े कर दिए हैं। "बगैर किसी के संरक्षण अपराधी के हौंसले कभी बुलंद नहीं हो सकते।" मछली साम्राज्य का नाम प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। मछली के अपराधों की परतें जिस तरह खुल रही हैं, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद किसी कारण से ही हैं। अपराधियों का नेटवर्क, उनकी गतिविधियाँ और उनका प्रभाव– यह सब इस ओर इशारा करता है कि इनके पीछे कोई न कोई बड़ा राजनीतिक सहारा जरूर मौजूद रहा है। प्रदेश की जनता के सामने अब यह सवाल सीधे-सीधे उठ खड़ा हुआ है कि आखिर किसके संरक्षण में इन अपराधियों ने वर्षों तक अपने कारनामों को अंजाम दिया? हकीकत ये है कि ये मछली परिवार सारंग की कृपा से सरसब्ज हुआ। मछली परिवार को यदि किसी का संरक्षण मिला है तो तय है कि वो कोई और नहीं, बल्कि इलाके का विधायक है। विधायक कौन है, किस दल का है ये पुलिस को भी पता है और जनता को भी, लेकिन मछली परिवार पुलिस के जाल में तब फंसा जब पानी सिर के ऊपर हो गया। (शेष पेज 3 पर)

गोविंद सिंह राजपूत पर छाया मंत्री पद जाने का सियासी तूफान

(पेज 1 का शेष)

कोर्ट की खरी-खरी सरकार भी सवालों में

हैरानी की बात यह रही कि इस मामले में जब राज्य सरकार की ओर से मंत्री के पक्ष में दलील दी गई, तो हाईकोर्ट ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को बचाने के लिए शासन की मशीनरी का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। मोहन यादव अब विपक्षी दलों और यहां तक कि मीडिया के निशाने पर आ गए हैं कि वे एक "दागी मंत्री" को क्यों संरक्षण दे रहे हैं?

सिंधिया खेमे पर भी सवाल

गोविंद सिंह राजपूत मध्यप्रदेश की राजनीति में एक मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी ताकत का सबसे बड़ा आधार है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब 2020 में सिंधिया कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आए थे, तब राजपूत भी उनके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अब जब राजपूत पर यह संकट गहराया है, तो एक बार फिर सिंधिया खेमे की राजनीति और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि सिंधिया के "गुर्गों" को भाजपा में जिस तरह प्रमुख पद दिए गए, क्या वह निर्णय अब पार्टी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है?

भाजपा में अंदरूनी साज़िश?

सूत्रों की मानें तो यह मुद्दा भाजपा के ही किसी नेता द्वारा हवा दी गई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सिंधिया समर्थक नेताओं और भाजपा के मूल संगठन के बीच टकराव चल रहा है। पुराने भाजपा नेताओं को यह बात खटकती रही है कि बाहर से आए नेताओं को सीधे मंत्री पद और संगठन में ऊंचा दर्जा कैसे दे दिया गया। ऐसे में, कुछ जानकारों का मानना है कि गोविंद सिंह राजपूत पर यह हमला कोई "बाहरी" षड्यंत्र नहीं बल्कि "घर का भेदी" कांड हो सकता है। यह भाजपा के अंदरूनी शक्ति संघर्ष का हिस्सा हो सकता है, जिसमें राजपूत को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

संगठन और सत्ता में हड़कंप

मंत्री पद पर मंडराते खतरे के कारण सिर्फ राजपूत ही नहीं, बल्कि पूरी पार्टी और संगठन परेशान है। अगर आरोप साबित होते हैं और राजपूत को इस्तीफा देना पड़ता है, तो यह भाजपा के लिए न सिर्फ छवि की क्षति होगी, बल्कि विपक्ष को एक मजबूत हथियार भी मिल जाएगा। विशेष रूप से कांग्रेस इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि "भ्रष्टाचार और पारदर्शिता" पर बड़े-बड़े भाषण देने वाली भाजपा अपने ही दागी नेताओं को क्यों बचा रही है? संगठन के भीतर भी अब यह चर्चा होने लगी है कि पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन अगर ऐसे नेता विवादों में घिरते रहे तो 2028 की राह मुश्किल हो सकती है।

मुख्यमंत्री की मुश्किलें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब खुद भी इस मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया के बाद यह सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से गोविंद सिंह राजपूत को क्यों बचा रहे हैं? क्या यह सिंधिया खेमे को खुश रखने की कोशिश है या फिर पार्टी में सामंजस्य बनाए रखने का एक प्रयास? जो भी हो, अब मुख्यमंत्री की स्थिति भी असहज हो गई है।

इस्तीफा या न्यायिक लड़ाई?

अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं। यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो गोविंद सिंह राजपूत को न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, बल्कि उनकी विधायकी भी रद्द हो सकती है। ऐसे में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है, जो भाजपा के लिए बहुत संवेदनशील साबित हो सकती है।

भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती

गोविंद सिंह राजपूत का संकट एक अकेले नेता की मुश्किल नहीं है, यह भाजपा की सरकार, संगठन और नीति निर्धारण की गंभीर परीक्षा है। यदि पार्टी इस मामले में पारदर्शिता नहीं अपनाती, तो आने वाले समय में जनता का भरोसा डगमगा सकता है। वहीं, अगर पार्टी कार्रवाई करती है, तो संगठन के भीतर का समीकरण बिगड़ सकता है, खासकर सिंधिया खेमे के साथ। अब देखना यह है कि भाजपा "न्याय" की ओर झुकती है या "न्यायपालिका" के दबाव में कार्रवाई करने पर मजबूर होती है। जो भी हो, गोविंद सिंह राजपूत की नाव इस समय भंवर में है और उसे किनारे तक पहुंचाने का रास्ता अब बहुत कठिन हो चुका है।

कड़क छवि और सटीक कार्यशैली वाले अफसर के कंधों पर अब प्रशासनिक चुनौतियों का भार

(पेज 1 का शेष)

केंद्र में प्रतिनियुक्ति के दौरान वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा नीति आयोग, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास और वित्त जैसे विभागों में उनकी सेवाओं को विशेष रूप से सराहा गया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है प्रभावी नीति निर्माण, टीम प्रबंधन और कठोर निर्णय लेने की क्षमता। यही वजह है कि उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ जैसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण राज्य के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है।

मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अफसर

सूत्रों की मानें तो विकास शील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विश्वस्त अफसरों में से एक हैं। दोनों के बीच प्रशासनिक समन्वय बेहतर माना जाता है। विष्णुदेव साय की सरकार अब स्थायित्व की दिशा में बढ़ रही है और ऐसे में उन्हें ऐसे अफसर की आवश्यकता थी जो न सिर्फ भरोसेमंद हो, बल्कि प्रशासनिक मशीनरी को अनुशासित भी कर सके। शील की नियुक्ति को सरकार की "सख्त लेकिन सजग प्रशासन" की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में राज्य में कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी और अफसरशाही में अनुशासनात्मक सुधार होंगे।

ये होंगे विकास शील के सामने प्रमुख मुद्दे

नक्सलवाद से निपटना- दक्षिण बस्तर समेत कई क्षेत्र आज भी नक्सल समस्या से जूझ रहे हैं। वहां विकास की गति धीमी है और शासन की पकड़ कमजोर। विकास शील को इन इलाकों में सुशासन, सुरक्षा और सेवाओं की पहुँच बढ़ाने की चुनौती होगी।

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन- केंद्र और राज्य की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं फाइलों तक सिमटी हुई हैं या फिर जमीन पर आधे-अधूरे तरीके से लागू हो रही हैं। विकास शील से उम्मीद है कि वे योजनाओं की मॉनिटरिंग सिस्टम को सुदृढ़ करेंगे।

राज्य की आर्थिक स्थिति- छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था संसाधनों पर आधारित है, लेकिन राजस्व संग्रह और निवेश के मोर्चे पर सुधार की आवश्यकता है। नए निवेशकों को आकर्षित करने, MSME को बढ़ावा देने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में उन्हें कार्य करना होगा।

भ्रष्टाचार पर लगाम- पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। विकास शील की छवि साफ-सुथरी मानी जाती है, ऐसे में उनकी नियुक्ति से यह संकेत गया है कि सरकार अब "भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस" की नीति पर काम करना चाहती है।

प्रशासनिक सुधार और फील्ड अफसरों की जवाबदेही- राज्य में जिलों और ब्लॉकों में कार्यरत अधिकारियों की कार्यप्रणाली सुधारने की आवश्यकता है। फील्ड अफसरों की जवाबदेही तय करना और सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी बनाना विकास शील की प्राथमिकताओं में रहेगा।

कार्यशैली कड़क लेकिन परिणामोन्मुख

विकास शील की कार्यशैली को लेकर सरकारी गलियारों में एक आम राय है। वे कड़क, अनुशासनप्रिय और नतीजे देने वाले अफसर हैं। वे अनावश्यक ढिलाई, राजनीति में हस्तक्षेप या ढुलमुल रवैये को बर्दाश्त नहीं करते। उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी मानते हैं कि शील स्पष्ट दिशा देते हैं और फिर समयबद्ध परिणाम की अपेक्षा करते हैं। वे बैठकों को केवल चर्चा का मंच नहीं, बल्कि "डिलीवरी मीटिंग" मानते हैं। यही कारण है कि उनके साथ काम करना आसान नहीं, लेकिन प्रेरक जरूर होता है।

आने वाला समय चुनौतीपूर्ण

हालांकि विकास शील के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे पद पर बिठाया गया है जहाँ उनसे सिर्फ नीतियों की बात नहीं होगी, बल्कि उनके क्रियान्वयन की समयबद्ध अपेक्षा भी होगी। राजनीतिक दबाव, फील्ड अधिकारियों की मनमानी, स्थानीय स्तर की गुटबाजी, और जनता की अपेक्षाएं। इन सभी के बीच संतुलन बनाकर चलना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वे अपनी कार्यशैली पर कायम रहते हैं, तो वे छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में एक मजबूत और यादगार मुख्य सचिव के रूप में दर्ज हो सकते हैं।

उम्मीदों पर खरे उतरने की चुनौती

विकास शील की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब परिणाम आधारित शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। विकास शील को अपने कार्यकाल में न केवल प्रशासनिक मशीनरी को नई दिशा देनी होगी, बल्कि जनता के बीच यह विश्वास भी कायम करना होगा कि "सरकार काम कर रही है। उनकी नियुक्ति से नौकरशाही में भी एक संदेश गया है कि अब काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा और ढिलाई बरतने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विकास शील इन उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं।

मंत्री विश्वास सारंग के संरक्षण से पनपा अपराध और मध्यप्रदेश की राजनीति और मछली कांड का सच

(पेज 1 का शेष)

पुलिस को भी मछली पकडने में लंबा समय लग गया। यानि कोई एक साल 8 महीना रहा।

विश्वास सारंग पर आरोपों की बौछार

इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सवाल खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग पर उठ रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सारिक और यासीन मछली ने जिस क्षेत्र में अपना अपराध साम्राज्य खड़ा किया, वही क्षेत्र विश्वास सारंग का विधानसभा क्षेत्र भी है। जनता का सवाल वाजिब है कि जब क्षेत्र में ऐसी आपराधिक गतिविधियाँ चल रही थीं, तो क्षेत्र के विधायक और मंत्री को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? पुलिस की जांच में भी अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, वे लगातार सारंग की ओर ही इशारा कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट में एक ही नाम प्रमुखता से सामने आया है कि सारिक और यासीन मछली को यह संरक्षण विश्वास सारंग से मिला।

मंत्री की बेचैनी और सफाई का सिलसिला

मामले की परतें खुलने के साथ ही मंत्री विश्वास सारंग की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। सूत्र बताते हैं कि वे लगातार पार्टी के बड़े नेताओं, पुलिस अधिकारियों और कानूनविदों से मिलकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि यदि कोई निर्दोष है, तो उसे बार-बार अपनी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जनता अब इस निष्कर्ष पर पहुँचने लगी है कि सारंग के डर और दबाव से ही इतने लंबे समय तक अपराधियों का साम्राज्य फलता-फूलता रहा।

मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की चुप्पी

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश में अपराधियों के संरक्षण का मामला सरकार के मंत्री तक जा पहुँचता है, तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आखिर चुप क्यों हैं? अब तक दोनों ही नेताओं ने न तो मंत्री सारंग से कोई सवाल-जवाब तलब किया और न ही कोई सार्वजनिक बयान दिया। यह चुप्पी अपने आप में

बहुत कुछ कहती है। क्या मुख्यमंत्री अपनी सरकार की बदनामी छुपाने के लिए एक विवादास्पद और बदनाम मंत्री पर पर्दा डाल रहे हैं? क्या पार्टी संगठन भी इस अपराध-राजनीति गठजोड़ की सच्चाई सामने आने से डर रहा है?

जनता का आक्रोश और विश्वास का संकट

मध्यप्रदेश की जनता इस पूरे घटनाक्रम को गहरी नजर से देख रही है। जनता को यह भलीभाँति समझ में आ गया है कि अपराधियों के हौसले किसी कारण से ही इतने बुलंद रहे हैं। जनता अब सवाल पूछ रही है। क्या सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने में सक्षम है? या फिर सरकार अपने ही मंत्री को बचाने में व्यस्त है? इस प्रकरण ने सरकार और संगठन की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। यदि समय रहते सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए, तो यह मामला आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री पर है कार्यवाही की बड़ी जिम्मेदारी

राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। जनता उनसे यह उम्मीद करती है कि वे अपने ही मंत्री पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएँगे। लेकिन यदि मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे रहते हैं, तो जनता यह मानने पर मजबूर होगी कि सरकार अपराधियों और उनके संरक्षकों को बचाने में लगी है। मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि अपराध पर पर्दा डालने से अपराध खत्म नहीं होता, बल्कि और अधिक पनपता है।

सारंग की सरपरस्ती में मछली से मगरमच्छ बना शारिक

राजधानी भोपाल का ये शारिक मछली कैसे मगरमच्छ बन गया। इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। दरअसल शारिक मछली के परिवार ने 42 साल पहले तालाबों से अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम शुरू किया था। इस मछली परिवार ने 1983 में सहकारी मछली पालन समिति बनाई। भोपाल के हथाईखेड़ा डैम सबसे पहले इस अपराधी परिवार ने कब्जा किया। वैसे तो ठेका 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन यह काम निरंतर जारी रहा, जबकि कलेक्टर ने इस मछली पालन समिति को अवैध घोषित कर दिया लेकिन सारंग की सरपरस्ती के कारण शारिक मछली का यह अवैध कारोबार निरंतर जारी रहा। इस अपराधी ने कोकता के अनंतपुरा इलाके में छह हजार स्क्वायर फीट की सरकारी जमीन कब्जा करके एक आलीशान कोठी भी बनाई जिसे हाल ही में सरकार ने बुलडोजर से गिराया। सवाल है कि एक मछली पकड़ने वाला इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया?

अपराध और राजनीति का खतरनाक गठजोड़

मध्यप्रदेश की जनता ने लंबे समय तक भाजपा पर भरोसा जताया है, क्योंकि पार्टी ने हमेशा सुशासन और पारदर्शिता का दावा किया। लेकिन यदि अपराधियों को मंत्री के संरक्षण में पनपने दिया गया, तो यह न केवल जनता के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या भी है। राजनीति और अपराध का गठजोड़ किसी भी समाज के लिए विनाशकारी होता है। एक ओर सरकार अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करती है, दूसरी ओर उसके ही मंत्री पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। यह विरोधाभास जनता की नजरों से छुपाया नहीं जा सकता।

कानून की निष्पक्षता पर प्रश्नचिंह

अब तक की जांच केवल औपचारिक प्रतीत हो रही है। पुलिस लगातार ऐसे तथ्यों को उजागर कर रही है, जिनमें मंत्री का नाम उभरकर सामने आता है, लेकिन कार्रवाई के स्तर पर चुप्पी साध ली जाती है। यह स्थिति कानून की निष्पक्षता और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरे प्रश्नचिंह खड़े करती है। यदि अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण सच है, तो फिर यह जांच केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगी। और यदि जांच में सच्चाई सामने आती है, तो सबसे पहले कार्रवाई उसी मंत्री पर होनी चाहिए, जो आरोपों के घेरे में हैं।

कांग्रेस ने कालेज प्रबंधन पर लगाए आरोप, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। मंडलम कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सोनकिया ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि शासकीय महाविद्यालय टिमरनी में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में पिछले दो वर्षों से क्षेत्रीय विधायक अभिजीत शाह को लगातार आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह न केवल जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं के खिलाफ भी है।जनप्रतिनिधि जनता और शासन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ऐसे में सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ताकि जनता की समस्याओं व अपेक्षाओं का सीधा संवाद स्थापित हो सके। इस संदर्भ में अनुभागीय अधिकारी टिमरनी के माध्यम से कलेक्टर हरदा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कॉलेज प्रबंधन पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही, भविष्य में इस प्रकार की

घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है। जितेंद्र सोनकिया, कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। सत्ता पक्ष के दबाव में बिना आवश्यकता के जनभागीदारी में नियुक्तियाँ की गईं, अपनी मर्जी से वेतन वृद्धि में विसंगतियाँ की गईं, जनभागीदारी शुल्क बढ़ाकर छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया। इन सभी मुद्दों को बेहद गंभीर बताते हुए ज्ञापन में कलेक्टर से संपूर्ण प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष जितेंद्र सोनकिया, सचिन सेठ, धर्मेंद्र जसपाल, शहजाद खान, शेंकी उपाध्याय, शिवम कनोजिया,अनीश शाह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आयु सीमा में छूट नहीं देने से तीन लाख अभ्यर्थी प्रभावित

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में आयोजित होने वाली पुलिस एएसआई भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट नहीं देने से क़रीब 03 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए अपात्र हो गए हैं। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि कोविड महामारी के कारण दो वर्ष तक बहुत सी परीक्षा नहीं हो सकी और तब सरकार ने स्वयं यह घोषणा की थी कि भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि परीक्षा की प्रक्रिया तय करने वालों को सरकार के बनाए नियम का या तो पता नहीं है या वह पालन नहीं करना चाहते। यह पहला मौका नहीं है जब किसी भर्ती प्रक्रिया में इस तरह के नियम बनाए गए हैं, इससे अभ्यर्थियों को नुक़सान हो। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि आयु सीमा में छूट का प्रावधान तत्काल लागू किया जाए ताकि लाखों छात्रों के साथ अन्याय न हो।

सम्पादकीय

भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर खेल मैदान तक पहुंचा

भारत और पाकिस्तान के संबंधों की जटिलता किसी से छिपी नहीं है। विभाजन के समय से ही दोनों देशों के बीच तनाव का इतिहास रहा है। युद्ध, आतंकवाद, सीमा विवाद और कूटनीतिक कटुता ने इस रिश्ते को लगातार प्रभावित किया है। यह तनाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा है, जिनमें खेल जगत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्रिकेट जैसे खेल, जो आपसी मेल-जोल और कूटनीतिक संबंधों को सुधारने का माध्यम बन सकते थे, अब तनाव का प्रतिबिंब बन चुके हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में खेल को राष्ट्रों के बीच सौहार्द्र और संवाद के एक सेतु के रूप में देखा जाता है। परंतु भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में खेल, विशेषकर क्रिकेट, अब राजनैतिक और सामरिक नीतियों की छाया में आ गया है। जब भी दोनों देशों के बीच कोई आतंकी घटना होती है या सीमा पर संघर्ष होता है, इसका सीधा असर दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों पर पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध पूरी तरह समाप्त कर दिए थे। इसके बाद से आज तक दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई है। दोनों टीमें केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स जैसे विश्व कप या एशिया कप जैसे बहुपक्षीय आयोजनों में ही आमने-सामने आती हैं। यही कारण है कि जब भी भारत-पाकिस्तान मैच होता है, तो वह सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता। वह राष्ट्र गर्व, राजनीतिक संदेश और जनभावनाओं का विस्फोट बन जाता है।

क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पर भी इस तनाव का गहरा असर पड़ा है। कई बार भारतीय खिलाड़ियों या टीमों ने पाकिस्तान जाकर टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार किया है और पाकिस्तान ने भी भारतीय खिलाड़ियों को वीजा देने से मना किया है। शूटिंग, कुश्ती, हॉकी और टेनिस जैसे खेलों में भी यह देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में जब भी भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी आमने-सामने आते हैं, तो मैदान का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद आईसीसी विश्व कप 2019 में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर भी विवाद हुआ। कई भारतीय राजनेताओं और क्रिकेट प्रशंसकों ने मांग की कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए। हालांकि बाद में भारत ने यह मैच खेला और जीत भी हासिल की, लेकिन यह बहस यही दिखाती है कि खेल और राजनीति अब पूरी तरह से एक-दूसरे में घुलमिल चुके हैं। भारत ने कई बार यह रुख अपनाया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को समाप्त नहीं करता, तब तक उसके साथ सामान्य संबंध बहाल नहीं किए जा सकते, चाहे वह व्यापार हो, सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो या खेल। इस कूटनीतिक नीति को "नो क्रिकेट टिल टेरर एंड्स" के रूप में जाना जाता है। इसके उलट पाकिस्तान बार-बार यह मांग करता रहा है कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाए और दोनों देशों के बीच खेलों के माध्यम से संवाद शुरू किया जाए। लेकिन भारत का स्पष्ट मत है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर प्रभावी कार्यवाही नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय श्रृंखला संभव नहीं है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के राजनीतिक और सैन्य संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हैं, सवाल यह उठता है कि क्या खेल एक पुल बन सकता है? क्या क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के जरिए जनता के स्तर पर आपसी समझ और सौहार्द्र को बढ़ाया जा सकता है?

सियासी गहमागहमी

मछली के जाल में बुरी तरह उलझ चुके हैं विश्वास सारंग

राजनीति की नदी में कई नेता मछुआरे बने घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुद जाल में फँस जाएँ तो बड़ा तमाशा बन जाता है। विश्वास सारंग भी इन दिनों कुछ ऐसे ही "राजनीतिक जाल" में बुरी तरह उलझे नजर आ रहे हैं न कोई किनारा दिख रहा है, न कोई दिशा। जाल भी ऐसा कि बाहर निकलने की जितनी कोशिश करें, उतना ही और फँसते चले जाएँ। आरोपों की मछलियाँ इधर-उधर फड़फड़ा रही हैं और जनभावनाओं का पानी दिन-ब-दिन गंदला होता जा रहा है। जिस जाल को कभी उन्होंने विपक्ष पर फेंका था, अब वही उनके चारों ओर कसता जा रहा है। भाषणों में बड़े-बड़े आदर्श, नैतिकता की बातें और विरोधियों पर तीखे वार। अब सब पर सवाल उठने लगे हैं। आलम यह है कि मीडिया वाले भी कैमरा लेकर हर कोण से उनकी "उलझन" का विश्लेषण कर रहे हैं, और सोशल मीडिया तो जैसे मछली बाजार ही बन चुका है। जहाँ हर किसी के पास अपनी-अपनी "पकड़" की कहानी है। विश्वास सारंग शायद भूल गए कि राजनीति में जाल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी बन सकता है। और अगर वक्त रहते नहीं संभले, तो मछली तो दूर, नाव भी पलट सकती है।

भाजपा नेताओं ने फिर शुरू की बेबाक बयानबाजी

भाजपा नेताओं की बयानबाजी अब किसी मौसम की तरह हो गई है कब गरज पड़े, कब बर्फ गिरा दें, कब गर्म हवाएं चला दें, कोई ठिकाना नहीं। विजय शाह के बयानबाजी का धुआं अभी ठीक से छंटा भी नहीं था कि कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा बयान ठोक दिया कि राजनीतिक तापमान फिर से उबलने लगा। अब इसे बयान देना कहें या मुँह का गियर फेल होना, तय करना मुश्किल है। कैलाश जी का बयान आया नहीं कि मीडिया वालों की तो जैसे दिवाली हो गई पैनल सज गए, एंकरों की भौंहें तन गईं, और जनता का मनोरंजन चालू हो गया। लेकिन असली शो तब शुरू हुआ जब विजय शाह ने इस बयान का ऐसा समर्थन ठोंका कि शर्म भी शरमा गई। बयान ऐसा कि लगे जैसे जनहित में नहीं, जन-मनोरंजन के लिए जारी किया गया हो। लगता है इन नेताओं ने बयान देने को ही राजनीति का असली धर्म समझ लिया है काम हो न हो, बयान जरूर हो। योजनाएँ जमीन पर उतरें न उतरें, जुमले आसमान में जरूर उड़ने चाहिए। जनता परेशान है कि मुद्दों पर बात कब होगी, और नेता परेशान हैं कि अगला बयान किस अंदाज में दें। आखिर, अगर राजनीति सर्कस है तो ये नेता उसमें जोकर नहीं, रिंग मास्टर बनने की होड़ में हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

भाजपा चाहे जितने भी झूठ और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अतिपिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को उनका पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं।

बिहार में अतिपिछड़ा समाज को मजबूत बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र' में ठोस वादे किए हैं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के किसानों को एक बार फिर से परेशान करने की तैयारी कर रही है। सोयाबीन की खरीद के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा है।

पिछले सालों में इस समय तक केंद्र सरकार को सोयाबीन खरीद का प्रस्ताव भेज दिया जाता था। पिछले साल 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और 25 अक्टूबर से सोयाबीन की MSP पर खरीद प्रारंभ हो गई थी।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

भारतीय राजनीति में प्रभावशाली नेता हैं सोनिया गांधी

समता पाठक/जगत प्रवाह

सोनिया गांधी, भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक सेवा दी। उनका जीवन एक साधारण इतालवी लड़की से भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने की प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने न केवल राजनीति में बल्कि भारतीय समाज में भी गहरा प्रभाव डाला है। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लूसियाना, वेनेतो नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका मूल नाम एदविग एंतोनिया अल्बीना माइनो था। उनके पिता का नाम स्टेफेनो माइनो और माता का नाम पाओला माइनो था। उनके पिता एक निर्माण कंपनी चलाते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस में एक फासीवादी सैनिक के रूप में भी काम कर चुके थे। सोनिया का पालन-पोषण एक रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इटली में ही हुई। बाद में, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड का रुख किया, जहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पास एक भाषा विद्यालय में अंग्रेजी भाषा सीखी।

सोनिया गांधी की किस्मत का रुख तब बदल गया जब 1965 में इंग्लैंड में उनकी मुलाकात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी से हुई। दोनों के बीच जल्द ही प्रेम हुआ और यह रिश्ता 1968 में विवाह में बदल गया। विवाह के बाद सोनिया भारत आई और एक पारंपरिक भारतीय बहू की तरह नेहरू-गांधी परिवार का हिस्सा बन गईं। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया और भारतीय परंपराओं को अपनाते हुए साधारण जीवन जीने लगीं। उन्होंने राजनीति से दूरी बनाकर रखी और एक गृहिणी के रूप में जीवन व्यतीत किया।

सोनिया गांधी ने लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उस समय मना कर दिया। कुछ वर्षों बाद, 1997 में सोनिया गांधी ने सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 1998 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पार्टी को नए सिरे से संगठित किया और 1999 के आम चुनाव में पार्टी की कमान संभाली।

सोनिया गांधी ने लगभग 22 वर्षों तक (1998–2017 और फिर 2019–2022 तक) कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी महिला ने इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व नहीं किया था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2004 और 2009 के आम चुनावों में शानदार जीत दर्ज की। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) का गठन हुआ और डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं के बावजूद यह पद अस्वीकार कर दिया, जिससे उनके त्याग और लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना हुई। उन्होंने 2004 से 2014 तक UPA चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया और सामाजिक योजनाओं जैसे मनरेगा, RTI, और मिड-डे मील योजना को प्रोत्साहित किया।

सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। अक्सर उन्हें विदेशी मूल का होने के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। कई विपक्षी दलों, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उनके विदेशी मूल पर सवाल उठाए और उन्हें भारत की राजनीति में विदेशी प्रभाव के रूप में दर्शाया। उनकी संपत्ति, उनके परिवार के विदेशी संपर्क, और कांग्रेस सरकार में हुए कुछ कथित घोटालों को लेकर भी विवाद हुए। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील जैसे मामलों में कांग्रेस सरकार आलोचना का केंद्र बनी, जिससे उनकी छवि को भी धक्का लगा। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य समय-समय पर चिंता का विषय रहा है। 2011 में वह इलाज के लिए अमेरिका गई थीं, हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। बाद के वर्षों में भी उन्हें कई बार चिकित्सा जाँच के लिए विदेश यात्रा करते देखा गया। सोनिया गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में संयम, धैर्य और संगठन कौशल का परिचय दिया। उन्होंने पार्टी के भीतर समन्वय बनाए रखा और गठबंधन की राजनीति में सफल रणनीति अपनाई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कीं।

जेनरेशन Z: एक ज्वालामुखी, जिसे दिशा चाहिए

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

आज दुनिया की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया की बहसों तक, अगर कोई पीढ़ी चर्चा के केंद्र में है, तो वह है जेनरेशन Z, यह 1997 से 2012 के बीच जन्मे उन युवाओं का समूह है, जिन्होंने इंटरनेट के साथ आँखें खोलीं। यह एक ऐसी पीढ़ी है जो ऊर्जा का ज्वालामुखी है, असीम, रचनात्मक और विस्फोटक। लेकिन अगर इसकी ऊर्जा को सही दिशा न दी जाए, तो यह विध्वंसक भी हो सकती है और खुद को भटका हुआ भी महसूस कर सकती है। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत इनका डिजिटल दिमाग है, जो सूचनाओं के महासागर में तैरना जानता है। वे जाति, रंग और लिंग की सीमाओं से परे सोचते हैं और विविधता को सहजता से स्वीकार करते हैं। उनमें सूचनाओं के ढेर से सच और गलत को पलक झपकते पहचानने की अद्भुत क्षमता है। लेकिन यही ताकत उनकी चुनौती भी है। हर चीज तुरंत पाने की चाहत उनमें धैर्य की कमी पैदा करती है। सूचनाओं की बाढ़ अक्सर उन्हें सतही ज्ञान देकर रोक देती है, जिससे वे मुद्दों की गहराई में उतरने से चूक जाते हैं। उनका उत्साह क्रांतिकारी है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति और प्रशासनिक दांव-पेंच की समझ अभी कच्ची है। यही कारण है कि उनका जोश कई बार ठोस परिणाम में नहीं बदल पाता और वे खुद को दिशाहीन महसूस करते हैं।

भटकाव का जोखिम: लद्दाख का सबक

इसका एक ज्वलंत उदाहरण हाल ही में लद्दाख में हुआ जन आंदोलन है। वहाँ के युवा, जो अपने संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे थे, उनकी ऊर्जा और इरादे नेक थे। लेकिन उनके आंदोलन को संबोधित करने के तरीके में एक खतरनाक मोड़ दिखा। कुछ विश्लेषकों और बाहरी ताकतों ने उनके प्रदर्शन को "Gen Z का नेपाल जैसा आंदोलन" बताकर एक खास नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश की। यह एक प्रयास था ताकि उनकी असली माँगों को भटकाकर उन्हें एक ऐसे आंदोलनकारी समूह के रूप में पेश किया जा सके जो सिर्फ सत्ता को चुनौती देना जानता है, समाधान देना नहीं।

यह घटना दिखाती है कि Gen Z की ऊर्जा कितनी संवेदनशील है। वे जितने साहसी हैं, उतने ही भावनात्मक भी। उन्हें सही मुद्दों पर एकजुट तो किया जा सकता है, लेकिन बाहरी ताकतें उनके इसी जोश को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे उनकी क्रांति दिशाहीन हो सकती है। यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि इस पीढ़ी की ऊर्जा को समझना और सही दिशा देना कितना महत्वपूर्ण है।

जब ऊर्जा ने व्यवस्था को चुनौती दी: वैश्विक सबक

यह सच है कि जब इस पीढ़ी की ऊर्जा एकजुट होती है, तो यह स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती देने की ताकत रखती है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश इसके हालिया उदाहरण हैं, लेकिन ये उदाहरण जीत के साथ-साथ एक गहरी सीख भी देते हैं:

नेपाल: युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लहर पैदा की, जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी और सत्ता के समीकरणों को प्रभावित किया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के बीच इस आक्रोश को एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव में बदलना अब भी एक बड़ी चुनौती है।

श्रीलंका: आर्थिक बदहाली से उपजे जन-आक्रोश का चेहरा बनकर इस पीढ़ी ने सरकार को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी, परंतु देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने और एक स्थिर शासन देने की जटिल जिम्मेदारी अब एक पहाड़ बनकर सामने खड़ी है।

बांग्लादेश: शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों के विशाल प्रदर्शनों ने प्रशासन को अपनी नीतियां बदलने पर विवश तो किया, लेकिन इन नीतिगत बदलावों को जमीनी हकीकत में उतारना और व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बनाना अभी बाकी है।

ये उदाहरण साबित करते हैं कि Gen Z में व्यवस्था को हिलाने की अभूतपूर्व क्षमता है। लेकिन असली चुनौती उस बदलाव को संभालना और देश को एक स्थिर भविष्य की ओर ले जाना है, जो केवल जोश से नहीं, बल्कि धैर्य, अनुभव और गहरी समझ से ही संभव है। परिवर्तन ले आना एक बात है, और उस परिवर्तन को राष्ट्र के लिए सफल बनाना बिलकुल दूसरी।

भारत के लिए संदेश और एक स्पष्ट रोडमैप

भारत, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, उसके लिए जेनरेशन Z एक अनमोल संपत्ति है। उनकी ऊर्जा को राष्ट्र-निर्माण में लगाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए एक स्पष्ट एक्शन प्लान की जरूरत है:

सतही ज्ञान से गहराई की ओर: उन्हें शॉर्टकट ज्ञान की जगह रिसर्च और डेटा-आधारित सोच के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

अनुभव का सेतु बनाना: अनुभवी पेशेवरों और नीति-निर्माताओं के साथ एक मेंटॉरशिप नेटवर्क तैयार करना होगा, ताकि वे जमीनी हकीकत को समझें।

मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता: डिजिटल दुनिया के दबाव से बचाने के लिए उन्हें ध्यान, खेल और वास्तविक सामाजिक जुड़ाव की ओर मोड़ना जरूरी है।

सिर्फ आंदोलन नहीं, समाधान भी: उन्हें सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और शासन प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना होगा।

नवाचार को मंच देना: उनके तकनीकी ज्ञान को स्टार्टअप्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सामाजिक उद्यमों की ओर मोड़कर एक स्थायी बदलाव की नींव रखी जा सकती है।

भविष्य नहीं, यह वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत हैं

जेनरेशन Z हमें याद दिलाती है कि बदलाव का इंजन हमेशा युवा ही होते हैं। अनुभव की कमी समय के साथ भर सकती है, लेकिन उनकी जिज्ञासा, साहस और दुनिया को बदलने की बेचैनी अनमोल है। यह पीढ़ी भटकी हुई नहीं है, बस उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। अगर हम इस ऊर्जा को सही मार्गदर्शन, गहरी शिक्षा और एक सकारात्मक मंच दे सकें, तो वे न केवल सत्ता बदलेंगे, बल्कि समाज में स्थायी विकास और सद्भाव भी लाएंगे। जेनरेशन Z सिर्फ भविष्य नहीं, यह वर्तमान की सबसे शक्तिशाली हकीकत है, और इस हकीकत को सही दिशा देना ही हमारे समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

शोध विकास संस्थानों के बजट में कमी, भारतीय शोधार्थियों को प्रोत्साहन की जरूरत

-प्रमोद भार्गव

पक्षियों के पंख अपने आप में संपूर्ण रूप में विकसित होते हैं, लेकिन हवा के बिना कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। यही स्थिति भारत में नवाचारी प्रयोगधर्मियों के साथ रही है। उनमें कल्पनाशील असीम क्षमताएं हैं, लेकिन कल्पनाओं को आकार देने के लिए प्रोत्साहन एवं वातावरण नहीं मिल पाता है। हालांकि 11 साल से सत्तारुढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वातावरण के निर्माण में अकल्पनीय काम किया है, किंतु अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनर्गल फैसलों के चलते जरूरी हो गया है कि हम अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थियों की मौलिक सोच को शोध की दिशा में प्रेरित करें। क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने नासा और नेशनल साइंस फाउंडेशन जैसे शोध विकास संस्थानों के बजट में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती कर दी है। दूसरी तरफ एच-1 बी वीजा की शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने की शर्त लगा दी है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वे दक्ष युवा भारतीय हैं, जो अमेरिका की आईटी कंपनियों में नौकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविश्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर मिलने में कमी आए। अतएव भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को बढ़ावा देना जरूरी है, जिनमें नवाचारी प्रतिभा है।

हालांकि नासा और नेशनल फाउंडेशन के बजट में भारी कटौती के बाद यूरोप ने 'चूज यूरोप फॉर साइंस' थीम पर मई-2025 में एक बैठक कर दुनिया के शोधार्थियों के लिए अपने संस्थानों के द्वार खोल दिए हैं। फ्रांस और भारत ने बजट बढ़ा दिया है। चीन पूर्व से ही स्कूल स्तर पर छात्रों की मौलिक सोच एवं नूतन आविष्कार की संभावनाओं की पहचान कर छात्रों को अनुसंधान की दिशा में उन्मुक्त करने लग गया है। भारत ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर एक लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। जिससे शोध की सोच को आविष्कार के रूप में साकार किया जा सके। अब छात्र वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अपने शोध आगे बढ़ा सकेंगे। वर्तमान और भविष्य के शोध एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, अंतरिक्ष विज्ञान, गणित और स्टेम साइंस के अनुसंधानों से जुड़े होंगे। आज के समय में नासा और भारत सुपर कंप्यूटर और डिजिटल संचार के माध्यमों में पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित संस्कृत को इनकी भाशा बनाने के संयुक्त अनुसंधान में लगे हैं। संस्कृत की भाषाई सटीकता और तार्किकता के चलते इसे कृत्रिम बुद्धि और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

संस्कृत की व्याकरण प्रणाली को तीन हजार से अधिक वर्ष पहले महर्षि पाणिनि ने संहिताबद्ध किया था। वैज्ञानिक इसे भाषाई विज्ञान का एक अद्वितीय नमूना मानते हैं। पाणिनि व्याकरण संस्कृत भाषा के लिए रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पर आधारित है। जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। यह व्याकरण एक अत्यधिक वैज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है। संस्कृत को इसी ने परिनिष्ठित और मानकीकृत किया है। पाणिनि की यह पद्धति दुनिया की पहली औपचारिक विधि मानी जाती है। इसके सहायक प्रतीकों (प्रत्यय) की प्रणाली ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि संस्कृत सुसंगत 'कंप्यूटर अनुकूल भाशा' हैं। इसलिए इसे एआई और रोबोटिक्स तकनीक के लिए उपयोगी भाषा माना जा रहा है। चूंकि भारतीय युवा अपनी मातृभाषा में प्राकृतिक रूप से दक्ष रहते हैं और इन भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसलिए उन्हें उपरोक्त क्षेत्रों में नए शोध करने में आसानी होगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी साहित्य सृजन में केवल पाश्चात्य लेखकों का ही बोलबाला है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक आविश्कारों से ही यह साहित्य भरा पड़ा है। भारत में भी इसी साहित्य का पाठ्य पुस्तकों में अनुकरण है। इस साहित्य में न तो हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की चर्चा है और न ही आविश्कारों की। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि हम खुद न अपने आविष्कारकों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और न ही उन्हें मान्यता देते हैं। इन प्रतिभाओं के साथ हमारा व्यवहार भी कमोबेश उपहासपूर्ण अभद्र रहता है। हालांकि अब निरंतर ऐसी प्रामाणिक सूचनाएं मीडिया में आ रही हैं, जिनसे निश्चित होता है कि प्राचीन भारत विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली था। संस्कृत ग्रंथों से यही ज्ञान अंग्रेजी, फारसी और अरबी भाशाओं में अनुदित होकर पश्चिम पहुंचा और वहां के कल्पनाशील जिज्ञासुओं ने भारतीय सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप में ढालकर अनेक आविश्कार व सिद्धांत गढ़कर पेटेंट करा लिए। इनमें से ज्यादातर पश्चिमी वैज्ञानिक उच्च शिक्षित नहीं थे। बल्कि उन्हें मनबुद्धि होने का दंड देकर विद्यालयों से कर दिया गया था।

आविष्कारक शोधार्थी को जिज्ञासु एवं कल्पनाशील होना जरूरी है। कोई शोधार्थी कितना भी शिक्षित क्यों न हो, वह कल्पना के बिना कोई मौलिक या नूतन आविष्कार नहीं कर सकता है। शिक्षा संस्थानों से विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसकी एक सीमा होती है, वह उतना ही बताती व सिखाती है, जितना हो चुका है। आविष्कार कल्पना की वह श्रृंखला है, जो हो चुके से आगे की अर्थात कुछ नितांत नूतन करने की जिज्ञासा को आधार-तल देती है। स्पश्ट है, आविष्कारक लेखक या नए सिद्धांतों के प्रतिपादकों को उच्च शिक्षित होने की कोई बाध्यकारी अड़चन पेश नहीं आनी चाहिए। अतएव हम जब लब्ध-प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की जीवन-गाथाओं को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि न तो वे उच्च शिक्षित थे, न ही वैज्ञानिक संस्थानों में काम करते थे और न ही उनके इर्द-गिर्द विज्ञान-सम्मत परिवेश था। उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। गोया, हम कह सकते हैं कि मौलिक प्रतिभा जिज्ञासु के अवचेतन में कहीं छिपी होती है। इसे पहचानकर गुणीजन या शिक्षक प्रोत्साहित कर कल्पना को पंख देने का माहौल दें तो भारत की ग्रामीण धरती से अनेक वैज्ञानिक-आविष्कारक निकल सकते हैं। इस दिशा में एक अच्छी पहल आईआईटी मद्रास में 'सोच का पाठ' पढ़ाने के पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ की है। यदि शिक्षक विद्यार्थी के अवचेतन में पैठ बनाए बैठे इस कल्पनाशील सोच को पहचानने में सफल होते हैं तो इस पाठ्यक्रम की सार्थकता निकट भविष्य में सिद्ध हो जाएगी।

दुनिया में वैज्ञानिक और अभियंता पैदा करने की दृश्टि से भारत का तीसरा स्थान है। भारतीय शोधार्थियों का वैश्विक प्रतिशत 2 हैं, सबसे उत्तम और चर्चित शोध-पत्रों की प्रस्तुति में हमारा योगदान 2.4 प्रतिशत है। लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि दुनिया के 29 प्रौद्योगिकी संपन्न देशों में भारत का स्थान पांचवां है। भारत ने उस प्रत्येक परिस्थिति को चुनौती और अवसर माना, जिसे दूसरे देशों के देने से मना कर दिया था। एक समय रूस ने भारत को अंतरिक्ष मिसाइल प्रक्षेपण से जुड़े क्रायोजनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया था। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे अपनी बुद्धि और देशज संशाधनों से विकसित किया और आज हम अंतरिक्ष में प्रमुख वैश्विक षक्ति हैं। इसी तरह 1987 में अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तब भौतिक शास्त्री विजय पांडुरंग भटकर ने इस स्थिति को एक चुनौती माना और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम स्वयं की मेधा से विकसित किया। अतएव ट्रंप के अवरोधों को हमें एक अवसर के रूप में देखने की जरूरत है।

स्वच्छ भारत अभियान को बने जन आंदोलनः श्याम बिहारी जायसवाल

-आनंद पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। नगर पालिक निगम चिरमिरी द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2025 और रजत जयंती वर्ष के अवसर पर दिनांक 25 सितम्बर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर एक दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम चिरमिरी में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी पार्क मालवीय नगर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पोंडी में सफाई अभियान और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता मित्रों ने अपने सामूहिक प्रयासों से आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई की और शहरवासियों को साफ-सुथरे वातावरण के महत्व का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया और नागरिकों से आह्वान किया कि स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाकर हर गली, हर मोहल्ला और हर पार्क को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन हमें समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और स्वच्छता की रोशनी पहुंचाने का प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शहर के सभी वार्डों में इसी तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि चिरमिरी को स्वच्छ और स्वस्थ नगर के रूप में विकसित किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों ने संकल्प लिया कि वे अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया "मेक-इन-सिलिकॉन" पोस्टर और वेबसाइट का शुभारंभ

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में "मेक-इन-सिलिकॉनः राष्ट्रीय सिंपोजियम ऑन एनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर" के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह संगोष्ठी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा देने और देश में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की पहल है। ट्रिपल आईटी-नया रायपुर के निदेशक प्रो. ओमप्रकाश व्यास ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी 7–8 नवम्बर 2025 को ट्रिपल आईटी-नया रायपुर में आयोजित होगी।

इसमें देशभर के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और नीति-निर्माता शामिल होंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को मिलकर नवाचार करना होगा और नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी। उनके अनुसार, स्वदेशी सेमीकंडक्टर अधोसंरचना ही भारत की डिजिटल और आर्थिक मजबूती की नींव है। यह आयोजन भारत सरकार के "सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन" और छत्तीसगढ़ सरकार की तकनीकी आत्मनिर्भरता की सोच के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे। इस अवसर पर संयोजक डॉ. मनोज मजूमदार, डॉ. दीपिका गुप्ता और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।

बिहार की 75 लाख महिलाओं को 7500 करोड़ की राशि वितरित

-अमित राय

जगत प्रवाह. बक्सर। 26 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7500 करोड़ की राशि का अंतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर भवन बक्सर में आयोजित किया गया। जिलाधिकारी बक्सर, डॉ. विद्यानंद सिंह एवं जीविका दीदियों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस योजना अंतर्गत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना है। हर समुदाय व हर वर्ग के परिवारों की महिलायें इसका लाभ ले सकती हैं। अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिये प्रारंभिक राशि 10 हजार दी जा रही है। बाद में आकलन कर 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है। पसंद के रोजगार हेतु प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। यह सामुदायिक सहकारिता आधारित योजना है। योजना से लाभान्वित कराने के लिये लाभुकों को पहले स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जायेगा। रोजगार के चयन एवं उसे शुरू करने में उन्हें स्थानीय समूहों की सहायता मिलेगी। लाभुकों को राज्य में सफलता पूर्वक कार्यरत 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख से अधिक जीविका दीदियों की संगठनात्मक व्यवस्था का सहयोग मिलेगा। प्रशिक्षण, उत्पादन में सहयोग के साथ-साथ महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिये गांव से शहरों तक हाट-बाजार भी विकसित किये जायेंगे। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता पर केन्द्रित इस योजना के माध्यम से राज्य एवं देश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। बक्सर जिलान्तर्गत जीविका समूह अंतर्गत 90,818 जीविका दीदियों के बीच प्रति 10,000 राशि की दर से 90,81,80,000 रुपए राशि का अंतरण किया गया।

स्कूल शिक्षा मंत्री के गृह जिले में विभागीय कार्रवाहियां बदहाल

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिला कहने को तो स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का गृह जिला है परंतु देखने में आ रहा है कि यहां जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी स्कूल शिक्षा मंत्री राव की छवि और विभागीय कार्यवाहियों को बदहाल करने में जी जान से जुट हैं। मानो उन्होंने विभागीय मंत्री राव को बदनाम करने का ठेका ले लिया हो। ताजा मामला यह है कि विगत वर्षों में वित्त विभाग और कोषालय अधिकारियों द्वारा की गई विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय चीचली की बड़े पैमाने पर वित्तीय जांच के उपरांत दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर बड़ी कार्यवाही और आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज कराने हेतु आयुक्त वित्त एवं कोष लेखा का पत्र 3 महीने पूर्व ही कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हो चुका है परंतु इसके बावजूद कि मामला स्कूल शिक्षा मंत्री की ग्रह विधानसभा के चीचली ब्लाक का है फिर भी अभी तक पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराया जा सका है। सूत्रों ने बताया है कि दोषी अधिकारी और कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से सांठ गांठ कर कार्यवाही करने वाले मामले की नोटशीट को जलेबी की तरह गोल-गोल घुमवा दिया है और उन्होंने इसके लिए आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखा है जबकि आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र आयुक्त वित्त विभाग ने एक ही साथ जारी हुआ है फिर जिले से अलग से पत्र पहुंचने की क्या आवश्यकता थी। मामला केवल अपराधिक प्रकरण दर्ज करने को टालने का बनाया जा रहा है। विभागीय चर्चाओं में बड़े पैमाने पर लेनदेन होना और कार्यवाही को टालने से जुड़े शिकायत और सतर्कता शाखा को बड़े पैमाने पर खेल की भूमिका में बताया जा रहा है।

टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का भारत को 100 गुना बड़ा वीजा शुल्क वृद्धि झटका

आखिर ट्रंप के निर्णय का कैसे जबाव दे पायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

-विजया पाठक

भारत और अमेरिका के रिश्तों को पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति और आर्थिक समीकरणों ने कई उतार-चढ़ावों से गुजारा है। एक ओर दोनों देशों को लोकतंत्र के साझेदार और वैश्विक रणनीतिक मित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं दूसरी ओर टैरिफ, व्यापार घाटा, और वीजा नीतियाँ अक्सर तनाव का कारण बन जाती हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिया गया निर्णय भारतीयों के लिए वीजा फीस को 88 हजार रुपये से बढ़ाकर लगभग 100 गुना तक कर देना न केवल अप्रत्याशित था बल्कि भारतीय युवाओं और उद्योग जगत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर जारी है और दूसरी ओर भारत रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों को गहरा कर रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या यह महज एक आर्थिक दबाव की रणनीति है या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यक्तिगत असहमति का परिणाम।

आखिर क्या है वीजा शुल्क वृद्धि का वास्तविक अर्थ

अमेरिका लंबे समय से यह शिकायत करता रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियाँ और पेशेवर H-1B जैसे वीजा प्रोग्राम का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी दृष्टिकोण से यह उनके नागरिकों की नौकरियाँ छीनने जैसा है। ट्रंप प्रशासन पहले भी "Hire American, Buy American" नीति के तहत वीजा प्रक्रिया को कठिन बनाता रहा है। लेकिन वीजा शुल्क को इतनी ऊँची छलांग पर पहुँचा देना एक तरह से भारतीयों के लिए अमेरिका की जमीन पर अवसरों को लगभग बंद कर देने जैसा है। भारतीय पेशेवरों के लिए यह निर्णय दोहरी मार है। पहला, भारी आर्थिक बोझ, और दूसरा, अनिश्चित भविष्य की आशंका। हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों के सपने जो अमेरिकी नौकरी और वहाँ के स्थायी अवसरों से जुड़े थे, अब अधर में लटकते दिख रहे हैं।

यह फैसला कहीं भारत की विदेश नीति का परिणाम तो नहीं

विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक समीकरणों से भी जुड़ा हो सकता है। हाल के वर्षों में भारत ने रूस से रक्षा समझौते किए, चीन के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाई और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अमेरिका की दृष्टि से यह एक संदेश है कि यदि भारत उसके हितों के खिलाफ जाता है तो उसे आर्थिक रूप से दबाव झेलना पड़ सकता है। इसलिए यह संभव है कि वीजा शुल्क वृद्धि केवल एक प्रशासनिक निर्णय न होकर रणनीतिक दबाव की नीति का हिस्सा हो।

ट्रंप का यह फैसला कहीं मोदी की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को कम करना तो नहीं

भारतीय विदेश मंत्रालय की चुप्पी ने बढ़ाई 140 करोड़ भारतीयों की चिंता

प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौतीपूर्ण प्रश्न

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा "भारत-अमेरिका की साझेदारी" को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का दावा करते आए हैं। ट्रंप के साथ उनकी कई मुलाकातें और 'Howdy Modi' जैसे बड़े आयोजन इस संबंध के प्रतीक माने गए। लेकिन अब जबकि ट्रंप ने भारतीय पेशेवरों के लिए इतना कठोर कदम उठाया है, तो मोदी के सामने गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वे अमेरिकी सरकार से इस पर बातचीत कर ढील दिला पाएँगे? अमेरिका में नौकरी कर रहे लाखों भारतीयों को वे किस प्रकार राहत देंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की युवा पीढ़ी को जो "अमेरिकी सपना" दिखाया गया था, उसकी हकीकत का सामना कैसे करेंगे? यह स्थिति मोदी के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक, दोनों ही स्तर पर कठिन है।

ट्रंप का यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रंजिश तो नहीं?

राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ट्रंप का यह फैसला कहीं मोदी के साथ व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम तो नहीं। मोदी ने हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर "बहुध्रुवीय दुनिया" की बात की है और अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने वाले देशों के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। इसके अलावा, ट्रंप स्वयं एक व्यावसायिक मानसिकता वाले नेता हैं। उनके लिए नीतियाँ अक्सर व्यक्तिगत समीकरणों और तात्कालिक हितों से संचालित होती हैं। यदि वीजा शुल्क वृद्धि को इस नजरिए से देखें, तो यह संभव है कि यह भारत को सीधा संदेश देने का प्रयास हो कि अमेरिका की प्राथमिकता केवल उसके अपने हित हैं, चाहे रिश्ते कितने भी निकट क्यों न दिखाए जाएँ।

भारतीय आईटी उद्योग और अर्थव्यवस्था पर असर

भारत का आईटी क्षेत्र लंबे समय से अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहा है। करोड़ों डॉलर का निर्यात और लाखों रोजगार इस उद्योग से जुड़े हैं। वीजा शुल्क वृद्धि से कंपनियों पर अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ेगा। इसका असर भारतीय कर्मचारियों की नियुक्तियों और वेतन संरचना पर पड़ सकता है। यह निर्णय भारत को भी एक चेतावनी देता है कि उसे अपने पेशेवरों के लिए अन्य वैश्विक बाजारों यूरोप, एशिया और अफ्रीका की ओर ध्यान देना होगा। "एक बाजार पर निर्भरता" की नीति अब टिकाऊ नहीं है।

विदेश मंत्रालय की चुप्पी से भारतीयों की बढ़ रही चिंता

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत का विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। संभवतः यह रणनीतिक चुप्पी हो, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि तत्काल प्रतिक्रिया देकर विवाद और बढ़े। लेकिन जनता और खासकर प्रभावित परिवारों में यह प्रश्न गूंज रहा है कि आखिर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतना बड़ा झटका दिया है, तो भारत की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। यह चुप्पी भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर भी कर सकती है। यदि सरकार अपने नागरिकों और पेशेवरों के हितों की रक्षा में मुखर नहीं होती, तो इसका संदेश यही जाएगा कि भारत अमेरिकी दबाव में है।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

सतत प्रगति पथ पर
छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री

बस्तर में बदलाव की बयार
- बस्तर में नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहारबस्तर में 24,000 करोड़ का निवेश विकास की नई उड़ान
- जांगला (बीजापुर) देश का पहला हेल्थ वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत की सौगात
- नगरनार स्टील प्लांट राष्ट्र को समर्पित
- रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना से विकास को नई रफ्तार
- 50,000 करोड़ की बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना बिजली, सिंचाई, रोजगार और पेयजल का मिलेगा लाभ

महिलाओं का सम्मान
- 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ
- 36 लाख महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन
- आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के लिए सभी पंचायत में 'महतारी सदन' का निर्माण

बेहतर भविष्य की आधारशिला
- राजधानी रायपुर में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी
- भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण व आईआईटी भिलाई की आधारशिला
- 30 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का विकास
- 32 हजार मेगावाट क्षमता के बिजली घरों के लिए एमओयू

कृषक कल्याण
- छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का सर्वाधिक दाम
- 20 माह में 1.25 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में
- 26 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि

आवास और सामाजिक सुरक्षा
- 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास
- 40 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल
- राज्य के शत्-प्रतिशत् गांवों का विद्युतीकरण
- खनिज क्षेत्रों में विकास हेतु डीएमएफ फंड की सौगात

सुगम आवागमन
- 47,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन
- 32 रेल्वे स्टेशनों का वर्ल्ड क्लास उन्नयन
- 40 हजार करोड़ से अधिक लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास
- रायपुर-विशाखापट्टनम एवं रायपुर-रांची-धनबाद एक्सप्रेस-वे
- जगदलपुर-रायपुर व अंबिकापुर-रायपुर हवाई सेवा प्रारंभ

जनजातीय सशक्तिकरण
- पीएम जनमन योजना 59 हजार परिवार लाभान्वित व 2,449 किमी सड़कें स्वीकृत
- धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान 6,691 ग्राम लाभान्वित

RO No. 13458/1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)